नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. UPHIN/25/A1698

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 023
दि. 23.05.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

'अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने बैठे': मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया, छेड़छाड़ करने वालों का क्या हो रहा अंजाम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 19 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में में 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया' की जगह 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन मेडिकल कॉलेज' ने ले ली है।

(जीएनएस)।

देवरियाः उत्तर प्रदेश में 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया' की जगह 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन मेडिकल कॉलेज' और 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' ने ले ली है। अब प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं, व्यापारी बेखौफ व्यापार कर रहे हैं और कोई भी गुंडा टैक्स वसूलने की हिम्मत नहीं कर सकता। प्रदेश की बेटियां नाइट शिफ्ट में भी काम कर रही हैं और यदि कोई शोहदा छेड़छाड़ का दुस्साहस करता है तो अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यह बात देवरिया में एक जनसभा में कही।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपये की लागत वाली 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। योगी ने कहा, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी? एक जिला, एक माफिया। हर जिले में एक माफिया होता था। त्योहारों से पहले अशांति फैल जाती थी, गरीबों की जमीनें हड़पी जा रही थीं, और गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। योजनाओं का वितरण भाई-भतीजावाद और पहचान के आधार पर किया जाता था।

उन्होंने कहा कि, 2017 से पहले माफिया सक्रिय थे। बेटियों और व्यापारियों में भय का माहौल था। शाम होते ही बेटियों को घरों में रहना पड़ता था और व्यापारी दुकानें बंद कर देते थे। आज उत्तर प्रदेश की पहचान बदल चुकी है। उन्होंने कहा, नौ साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि देवरिया में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। और मुझे खुशी है कि आज देवरिया में पूज्य महर्षि देवरहा बाबा के नाम पर एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा, हम सभी जानते हैं कि 2014 के बाद 'नए भारत' की जो परिकल्पना हम आज देख रहे हैं, वह प्रधानमंत्री के नेतृत्व

और उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है, जो विकास को प्राथमिकता देती है। उन्होंने यूपी की अपनी सरकार के बारे में कहा कि, यह सरकार समस्याओं को टालने वाली नहीं, बल्कि समाधान देने वाली सरकार है। हम समस्याएं नहीं, समाधान देते हैं, तभी जनता जनार्दन हमें चुनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश ने विकास की नई गति पकड़ी है और अब विकास की यह यात्रा रुकने वाली नहीं है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता

सीएम योगी ने कहा, काफी समय बाद आज मुझे देवरिया आने का अवसर मिला है। इस अवसर पर, देवरिया जिले को, और विशेष रूप से तीन विधानसभा क्षेत्रों को, 655 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है। उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने तेजी से इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को प्राथमिकता दी, क्योंकि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी ही तेजी से आम जनता तक पहुंचेगा।

देवरिया का कनेक्टिविटी बढ़ गई

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि, जब वे गोरखपुर के सांसद थे तब गोरखपुर से देवरिया तक सड़कें बदहाल थीं, कई हिस्सों में सिंगल लेन मार्ग था। लेकिन आज वही देवरिया फोर लेन कनेक्टिविटी से जुड़ चुका है। यहां से गोरखपुर पहुंचने का समय घट गया है। देवरिया से बलिया तक सड़क परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं। सीएम योगी ने कहा कि अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर, पुल और मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार व निवेश की नींव होते हैं। इसी सोच के तहत देवरिया से कसया, बरहज मार्ग, फ्लाईओवर और अन्य पुलों के लिए सरकार ने राशि स्वीकृत की है।

भारत-साइप्रस रिश्तों को मिला रणनीतिक साझेदारी का दर्जा, पीएम मोदी बोले- निवेश दोगुना करेंगे

(जीएनएस)।

नई दिल्ली। पीएम नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलिड्स के साथ विस्तृत द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में दोनों देशों ने भारत-साइप्रस संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का औपचारिक दर्जा देने का महत्वपूर्ण ऐलान किया।

यूरोपीय संघ का समुद्री द्वार समझे जाने वाले साइप्रस ईयू का छठा देश है जिसके साथ भारत ने अपने संबंधों को यह दर्जा दिया है। आज की बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोध और व्यापार सहयोग को नई गति देने के लिए संयुक्त टास्क फोर्स गठित करने का फैसला लिया गया।

संयुक्त प्रेस संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 'पिछले दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो चुका है। हमारा लक्ष्य अगले पांच वर्षों में इसे फिर से दोगुना करना है। इसी

लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंध को रणनीतिक साझेदारी में ऊंचा उठा रहे हैं।'

मोदी ने दोनों देशों के बीच दोस्ती को 'मजबूत और भविष्योन्मुखी' बताया। उन्होंने कहा कि भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते के बाद साइप्रस के माध्यम से व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग के नए द्वार खुलेंगे। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के संकट और यूक्रेन युद्ध पर भी गहन चर्चा की।

पीएम मोदी ने भारत के इस मत को फिर दोहराया कि उक्त दोनों क्षेत्रों में शांति स्थापना और संघर्ष के शीघ्र समाप्ति के सभी प्रयासों का समर्थन करता रहेगा। दोनों पक्षों ने वैश्विक संस्थाओं (यूएन, यूएनएससी आदि) के सुधार पर भी एकमत जताया और कहा कि बढ़ती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए यह सुधार अत्यंत आवश्यक है।

यह रणनीतिक साझेदारी ऐसे समय में हुई है जब तुर्की पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा और सैन्य संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है। पिछले वर्ष आपरेशन सिंदूर में यह बात सामने आई कि तुर्की ने पाकिस्तान को पूरा समर्थन दिया है। दूसरी तरफ साइप्रस लंबे समय से तुर्की के साथ क्षेत्रीय विवाद और तनाव में फंसा हुआ है।

हालांकि, भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को साफ-साफ कहा कि भारत और साइप्रस के बीच बढ़ते संबंध किसी तीसरे देश के विरुद्ध नहीं हैं। वैसे दोनों देश सुरक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं, जिसमें समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी कार्रवाई शामिल हैं। शुक्रवार को उच्चस्तरीय बैठक में भी रक्षा सहयोग एक अहम मुद्दा रहा है।

दोनों देश रक्षा क्षेत्र में सहयोग का एक रोडमैप बना रहे हैं।साइप्रस का भारत के लिए खास सामरिक महत्व है क्योंकि यह यूरोप का महत्वपूर्ण समुद्री द्वार माना जाता है। बदलते वैश्विक माहौल में भारत और ईयू के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं। पीएम मोदी हाल ही में चार यूरोपीय देशों की यात्रा के बाद भारत लौटे हैं।

तीन दिवसीय भारत के दौरे पर साइप्रस के राष्ट्रपति

साइप्रस राष्ट्रपति का तीन दिवसीय भारत दौरा दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक संतुलन और बहुआयामी साझेदारी को नई दिशा दे सकता है। पीएम मोदी ने वर्ष 2025 में साइप्रस की आधिकारिक यात्रा की थी, जिसने दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास को और मजबूत किया था। तब से लेकर अब तक आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों में निरंतर प्रगति हुई है।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को यहां

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के रूप में नौ मई को शपथ लेने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री से अधिकारी की यह पहली मुलाकात है।

पीएम मोदी के 'रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इनफॉर्म' मंत्र से किसानों के जीवन में भरेंगे खुशियां- केंद्रीय कृषि मंत्री

किसान-गरीब को भटकना नहीं पड़े, शिकायत निवारण को दें वरीयता- श्री शिवराज सिंह चौहान

नियम-प्रक्रिया को बनाएं सरल; एआई, डेटा और डिजिटल गवर्नेंस से कृषि-ग्रामीण विकास को देंगे नई धार- श्री शिवराज

कोर्ट केस, फाइल कल्चर और ड्राफ्टिंग पर श्री शिवराज सिंह का बड़ा सुधार एजेंडा

हर महीने होगी समीक्षा, केवल डिस्पोजल नहीं, जमीन पर समाधान चाहिए- श्री शिवराज सिंह

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' पर सवार है कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय- श्री शिवराज सिंह चौहान

2047 विजन, राज्यों से साझेदारी और 12 साल की उपलब्धियों के प्रस्तुतीकरण पर श्री शिवराज सिंह ने दिया जोर

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुवार शाम मंत्रिपरिषद की बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों के पालन को लेकर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अगले ही दिन आज अपने दोनों मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक लेकर साफ कहा कि सरकार का काम फाइलों में नहीं, जनता के जीवन में दिखना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसान, गरीब, ग्रामीण और आम नागरिक को योजनाओं का लाभ पाने या शिकायतों के समाधान के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए योजनाबद्ध, समयबद्ध और परिणाममुखी व्यवस्था तुरंत खड़ी की जाए।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आम आदमी को लड़ना न पड़े, उसे

दर-दर भटकना न पड़े और उसे योजनाओं का लाभ सहज, सरल और समय पर मिलना चाहिए। इसी को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कृषि, ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन और आईसीएआर समेत संबंधित इकाइयों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत, प्रभावी और जवाबदेह बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि अभी विभिन्न योजनाओं और विभागों में शिकायतों के निपटारे की अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं, जैसे अलग पोर्टल, अलग तंत्र और अलग प्रणाली, लेकिन अब इस व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी और परिणामकारी बनाने की जरूरत है। इसके लिए कृषि और ग्रामीण विकास, दोनों विभागों में कम से कम 10-10 अधिकारियों की टीम गठित करने को कहा गया, जो प्रतिदिन शिकायतों, जनसमस्याओं, पत्रों, जनप्रतिनिधियों के प्रतिवेदनों और विभिन्न पोर्टलों पर आई समस्याओं की समीक्षा करे।

श्री चौहान ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि शिकायतों का समाधान केवल कागज पर 'डिस्पोजल' दिखाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह देखा जाए कि लाभार्थी को वास्तविक राहत मिली या नहीं, योजना का लाभ वास्तव में पहुंचा या नहीं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि रिकॉर्ड में वितरण दिख रहा हो लेकिन जमीन पर लाभार्थी को कुछ मिला ही न हो।

बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने अपने उस अनुभव का भी उल्लेख किया, जिसमें लाभार्थियों को फोन कर सत्यापन करने पर कुछ मामलों में कागज और वास्तविकता के बीच अंतर सामने आया था। उन्होंने साफ कहा कि यह समस्या आसान नहीं, बल्कि जटिल है, इसलिए शिकायतों की प्रकृति, क्षेत्रवार प्रवृत्ति और योजनावार अड़चनों की पहचान कर तंत्र में आवश्यक बदलाव करना होगा।

उन्होंने निर्देश दिया कि हर महीने शिकायत निवारण व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि महीने के पहले सोमवार को समीक्षा की जाएगी।

दिल्ली-एनसीआर वालों के लिए अगले 5 दिन भारी, भीषण गर्मी के बीच आईएमडी की नई चेतावनी

(जीएनएस)।

पूरे उत्तर भारत में इस वक्त प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सूरज देवता ऐसे तेवर दिखा रहे हैं कि कई शहरों में अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं। दिल्ली-एनसीआर के लोगों का तो गर्मी से बुरा हाल हो चुका है। अब आलम यह है कि दिन तो दिन, रातें भी इतनी गर्म हो रही हैं कि कूलर-एसी सब जवाब दे रहे हैं। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है-आखिर इस झुलसाने वाली गर्मी से राहत कब मिलेगी और बादल कब बरसेंगे?

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, आज (23 मई) भी दिल्ली-एनसीआर के लोगों को भयंकर गर्मी और लू का टॉर्चर झेलना पड़ेगा। आज आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और तेज धूप सीधे बदन को झुलसाएगी। दिन के वक्त 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी गर्म हवाएं (लू) चलेंगी, जिनकी गति बीच-बीच में 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। आज अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान भी 35 डिग्री के करीब बना रहेगा, जिससे रात में भी चैन मिलना मुश्किल है।

अगर आपको लग रहा है कि कल रविवार को कुछ राहत मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 24 मई को गर्मी का प्रकोप और बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने कल के लिए भी 'ऑरेंज अलर्ट' जारी रखा है हालांकि, कल उत्तर दिल्ली, उत्तर-पश्चिम दिल्ली, पश्चिम दिल्ली और नई दिल्ली जैसे कुछ इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सुबह या शाम के वक्त गरज-चमक के साथ धूल भरी आंधी या थंडरी डेवलपमेंट की हल्की संभावना जरूर जताई गई है, लेकिन इससे तापमान में कमी नहीं आएगी, बल्कि उमस और बढ़ सकती है। कल से पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

पीएम मोदी संग साइप्रस राष्ट्रपति की सेल्फी ने बटोरी सुर्खियां, हैदराबाद हाउस में दिखी खास दोस्ती

साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिड्स भारत दौरे पर हैं। उन्होंने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। राष्ट्रपति ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और मुंबई में एनएसई की घंटी बजाई। यह दौरा दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग को और मजबूत करेगा। निकोस क्रिस्टोडौलिड्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शुक्रवार को नई दिल्ली में मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच एक बहुत ही दोस्ताना पल देखने को मिला।

आरके पुरम से लेकर संगम विहार तक घंटों पावर कट

दिल्ली-एनसीआर में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण इस समय पावर ग्रिड्स पर लोड बढ़ गया है। ऐसे में तकनीकी ब्लास्ट से बचने के लिए बीएसईएस राजधानी (BRPL) ग्रिड और ट्रांसफार्मर प्रणालियों का Preventive Mantenance करने जा रही है।

बंगाल: पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले दुकानदार को मिली जान से मारने की धमकी, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आई कॉल

(जीएनएस)।

कोलकाता। बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान झाड़ग्राम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले दुकानदार विक्रम साहू को जान से मारने की धमकी मिली है। दुकानदार की ओर से दावा किया गया कि पिछले कुछ दिनों से उसे पाकिस्तान और बांग्लादेश से रोजाना धमकी भरे काल आ रहे हैं।

साहू ने कहा कि मुझे पाकिस्तान से वीडियो और फोन ल के जरिए बार-बार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। वे मुझे बम से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। वह और उनका परिवार अंतरराष्ट्रीय नंबरों से आ रही इन धमकियों से खौफ में हैं।

साहू को पुलिस सुरक्षा भी मुहैया कराई गई

साहू ने कहा कि वह अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित है क्योंकि उन्हें डर है कि फोन करने वाले उसके साथ कोई साजिश रच सकते हैं। वहीं, पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। साहू को पुलिस सुरक्षा

भी मुहैया कराई गई है।

पुलिसकर्मी को उनकी सुरक्षा में तैनात किया गया है। मालूम हो कि हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने झारखंड की सीमा से सटे झाड़ग्राम जिले में चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद पास में स्थित विक्रम साहू की दुकान पर जाकर 10 रुपये की झालमुड़ी खरीदकर खाई थी।

जिसके बाद विक्रम साहू रातोंरात सुर्खियों में आ गए थे। झालमुड़ी की खरीदारी के दौरान दुकानदार विक्रम साहू और पीएम मोदी के बीच हुई बातचीत पूरे चुनाव में चर्चा का विषय बन गई थी। हालांकि, रातोंरात मिली यह शोहरत अब उसके लिए मुसीबत बन गई है।

वीडियो काल पर मिली धमकी

साहू ने कहा कि जो लोग मुझे वीडियो काल कर रहे हैं, वे मुझे डराने के लिए खौफनाक इशारे कर रहे हैं और हथियार भी दिखा रहे हैं। मुझे चेतावनी दी जा रही है कि तुम्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

साहू ने बताया कि उसने कई काल नहीं उठाए लेकिन फोन की घंटी बजनी बंद नहीं हुई।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

देवरिया-कसया मार्ग होगा फोरलेन, 292 करोड़ रुपये होंगे खर्च; सीएम योगी ने परियोजना की रखी आधारशिला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया-कसया मार्ग को फोरलेन बनाने के लिए 292 करोड़ रुपये की परियोजना का शिलान्यास किया।

देवरिया कसया मार्ग के निर्माण के लिए 292 करोड़ 06 लाख 66हजार होगे खर्च

भीमपुर में आयोजित भव्य समारोह के बीच परियोजना की रखी आधारशिला

संवाद सूत्र, रामपुर कारखाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 292 करोड़ 6 लाख 66 हजार की लागत से देवरिया-कसया मार्ग फोरलेन निर्माण लिए भव्य समारोह के बीच आधारशिला रखी। इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह रहा। ग्रामीणों का कहना है कि देवरिया-कसया मार्ग फोरलेन बनने से नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त होगा।

अंतर्राष्ट्रीय स्थल कुशीनगर को जोड़ने वाला देवरिया कसया मार्ग काफी दिनों से सिंगल मार्ग के रूप में था। जिस पर रोज हजारों की संख्या में दो पहिया चार पहिया वाहन चलते हैं। सिंगल मार्ग होने के चलते इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती थी। जिसको लेकर शासन ने इस मार्ग को फोरलेन में बदलने का निर्णय लिया।

इसके निर्माण होने से जहां विकास को आयाम मिलेगा वहीं आसपास के लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने

का अवसर मिलेगा। शासन ने प्रथम किस्त के रूप में 102 .22 करोड़ रूपया अवमुक्त कर दिया है ।फोरलेन निर्माण होने पर इसकी चौड़ाई 15 मी होगी।

जिसमें प्रत्येक लेने की चौड़ाई 7.50 मी होगी तथा बीच में दो मी चौड़ाई में डिवाइडर बनाने का कार्य किया जाएगा। इसके संपूर्ण निर्माण के लिए 292 करोड़ 06 लाख 66हजार की स्वीकृति प्रदान की गई है। नदी पर 106.88 मीटर लंबा तथा 11.50 मीटर चौड़ाई का पुल टू लेन में तैयार किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड को नामित किया गया है। क्षेत्रीय लोगों में फोर लेन निर्माण से यातायात सुगम होगा। जिसका सपना मुख्यमंत्री ने निर्माण की आधारशिला रख कर साकार कर दिया।

फोर लेन निर्माण से व्यापार के दिशा में व्यवसाईयों को बहुत लाभ मिलेगा तथा आम जनमानस को गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर की दूरी तय करने में कम समय के साथ-साथ कम ईंधन भी लगेगा। **अजीत सिंह, भाजपा नेता, बैकुंठपुर, रामपुर कारखाना**

फोर लेन पर चलना हम लोगों के लिए सपना जैसा था। मगर मुख्यमंत्री ने इस सपने को साकार करने का कार्य किया है।- **पंकज सिंह, ग्राम प्रधान, भगौतीपुर, रामपुर कारखाना**

देवरिया कसया फोर लेन मार्ग का निर्माण विकसित भारत की दिशा में एक अहम प्रयास है। जो भाजपा के शासन में पूरा होने जा रहा है।- **रविंद्र सिंह, ग्रामीण, मुंडेरा बाबू तरकुलवा**

फोर लेन का निर्माण किसान, मजदूर, व्यापारी तथा आम लोगों के लिए हित में है। जिससे विकास को गति मिलेगी। बिहार तक की यात्रा सुगम होगी।- **राजू सिंह, ग्राम प्रधान, रामपुर चंद्रभान, रामपुर कारखाना**

लखनऊ में पेंशन अदालत सह जीवन प्रमाण कैम्प का आयोजन

(जीएनएस)।

नियंत्रक संचार लेखा, उत्तर प्रदेश (पूर्व) लखनऊ द्वारा पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग तथा संचार मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली से प्राप्त निदेशों के अनुपालन में दिनांक 21 मई, 2026 को, नियंत्रक संचार लेखा उ०प्र० पूर्व कार्यालय परिसर लखनऊ में दूरसंचार पेंशनभोगियों के लिए पेंशन अदालत एवं जीवन प्रमाण कैम्प का अयोजन किया गया '

कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्र गीत 'वन्दे मातरम' के साथ किया गया ' कार्यक्रम में उपस्थित सभी पेंशनभोगियों का पुष्पमालाओं के साथ स्वागत किया गया । अपने संबोधन में नियंत्रक श्री मनीष कुमार गुप्ता ने कहा कि पेंशनभोगियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाना चाहिए एवं उनके द्वारा राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान का सम्मान करना चाहिए ' उन्होंने SAMPANN प्लेटफॉर्म की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला जिसके माध्यम से अब पेंशन सीधे पेंशन भोगी के खाते मे जाती है जैसे सेवा के दौरान उनका वेतन जाता था साथ ही प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार के शिविरों के आयोजन पर भी बल दिया।

अदालत की कार्यवाही के दौरान दूरसंचार पेंशनभोगियों के लंबित प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा पेंशनभोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाए गए और नवीनतम पहचान पत्र भी वितरित किए गए।

इस आयोजन में कार्यालय की उप नियंत्रक सुश्री प्रज्ञा ठाकुर, लेखाधिकारी श्रीमती संवेदना सिंह, सहायक लेखाधिकारी श्री अम्बरीश कुमार सहित अन्य कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंत में पेंशनर्स संघ के प्रांतीय सचिव श्री जे.एन.दुबे, प्रांतीय कोषाध्यक्ष श्री के.पी.अवस्थी , श्री प्रकाश चन्द्र सहित सभी पेंशनभोगियों तथा कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया ' कार्यक्रम का समापन 'राष्ट्रगान' के साथ किया गया '

यात्रियों की राह आसान बनाएगी योगी सरकार, मेट्रो स्टेशनों के पास किराये पर मिलेंगी ऐप आधारित साइकिलें

(जीएनएस)।

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने मेट्रो वाले शहरों में आमजन का सफर और आसान व सुविधाजनक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने में होने वाली दिक्कतों को खत्म करने के लिए सरकार ने 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक में मेट्रो यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल और सस्ती सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेट्रो स्टेशनों के पास मोबाइल एप आधारित साइकिल और ई-साइकिल किराए पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जाएगी। इससे खासकर छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और दैनिक यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

प्रदूषण कम करने में मिलेगी मदद

बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने और वहां से गंतव्य तक जाने की

सुविधा जितनी बेहतर होगी, उतना ही आम जनता का रुझान मेट्रो की ओर बढ़ेगा। इसके लिए मेट्रो स्टेशनों के आसपास पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था विकसित करने, अंडरग्राउंड पार्किंग की संभावनाएं तलाशने और खाली भूखंडों पर पीपीपी मॉडल के तहत पार्किंग निर्माण की योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मेट्रो रूट के समानांतर सिटी बसों का संचालन न किया जाए, ताकि मेट्रो सेवाओं की उपयोगिता बढ़े और यात्री संख्या में इजाफा हो सके। मेट्रो केवल तेज और सुरक्षित यात्रा का माध्यम नहीं है, बल्कि यह प्रदूषण कम करने और लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है।

बैठक में यह भी तय किया गया कि मेट्रो के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। लोगों को बताया जाएगा कि निजी वाहनों की तुलना में मेट्रो यात्रा समय, धन और ईंधन की बचत करने के साथ-साथ शहरों में ट्रैफिक दबाव कम करने में भी सहायक है।

बैठक में प्रमुख सचिव आवास पी. गुरुप्रसाद, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, मंडलायुक्त लखनऊ विजय विश्वास पंत और यूपी मेट्रो के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार आदि उपस्थित थे।

यूपी सरकार की सक्रियता से दो साल बाद परिजनों को मिला लापता मूक-बधिर बालक, भावुक होकर सीएम योगी का जताया आभार

(जीएनएस)।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में बाल संरक्षण और पुनर्वास व्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। इसी संवेदनशील कार्यशैली का एक भावुक उदाहरण उस समय सामने आया, जब लगभग दो वर्षों से घर से लापता एक मूक-बधिर बालक को राजकीय बालगृह (बालक), मोहान रोड, लखनऊ के प्रयासों से उसके परिवार से मिलवाया गया।

परिवार ने जिस बेटे के लौटने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी, उसे योगी सरकार की सक्रिय व्यवस्था और अधिकारियों की संवेदनशीलता ने फिर से अपने परिजनों से मिला दिया। शुक्रवार को जब यह बालक पश्चिम बंगाल से आए परिजनों को सौंपा गया तो भावुक होकर उन्होंने योगी सरकार को शुक्रिया कहा।

बालगृह प्रशासन ने नहीं मानी हार

दरअसल, बाल कल्याण समिति मेरठ के आदेश पर 12 सितंबर 2025 को करीब 13 वर्षीय एक मूक-बधिर बालक को राजकीय बालगृह (बालक), मोहान रोड में प्रवेश दिलाया गया था।

बालक बोल और सुन नहीं सकता था, इसलिए वह अपना नाम, पता या परिवार की कोई जानकारी

देने में असमर्थ था। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद बालगृह प्रशासन ने उसकी पहचान जानने के प्रयास लगातार जारी रखे। बालक की देखभाल के साथ-साथ उसकी पहचान पता लगाने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर लगातार काम किया गया।

आधार कार्ड से खुला घर का पता

इसी बीच इस बालक का आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया शुरू की गई। जब बालक ने स्कैन मशीन पर उंगलियों के निशान दिए तो पूर्व में बने आधार कार्ड का विवरण सामने आ गया। इस आधार कार्ड से बालक का पता पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के ग्राम गंगासार का मिला।

इसके बाद बालगृह प्रशासन ने संबंधित क्षेत्र में संपर्क स्थापित कर परिवार तक सूचना पहुंचाई। जानकारी मिलते ही परिवार भावुक हो उठा, क्योंकि रमजान नाम का यह बालक करीब दो वर्षों से लापता था और परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे इस पूरी प्रक्रिया में उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी एवं उप निदेशक मेरठ मंडल पुनीत मिश्रा का विशेष सहयोग रहा। अधिकारियों की सक्रियता और मानवीय संवेदनाओं ने एक बिछड़े परिवार को फिर से जोड़ने का कार्य किया।

बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास को प्राथमिकता

महिला कल्याण निदेशालय की निदेशक सी. इंदुमति ने बताया कि योगी सरकार बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि मूक-बधिर बालक की पहचान स्थापित करना आसान नहीं था, लेकिन टीम ने लगातार प्रयास जारी रखे। आधुनिक तकनीक और आधार कार्ड की मदद से आखिरकार बालक को उसके परिवार तक पहुंचाना संभव हो सका। उन्होंने कहा कि यह केवल प्रशासनिक सफलता नहीं, बल्कि संवेदनशील शासन और मानवता की बड़ी मिसाल है।

लखनऊ के गोमती नगर में गला दबाकर की गई थी महिला संविदाकर्मी की हत्या, प्रेमी गिरफ्तार

(जीएनएस)।

लखनऊ। गोमतीनगर स्थित विकासखंड-4 इलाके में किराए के मकान में गोसाईगंज की सीएचसी में तैनात 30 वर्षीय निशा की हत्या गला दबाकर की गई थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में उसके प्रेमी हरदोई के संडीला स्थित जनीगांव निवासी दीपांशु सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपित के खिलाफ मृतका के ससुर रामदास ने मुकदमा दर्ज कराया था।

डीसीपी पूर्वी दीक्षा शर्मा ने बताया कि निशा देवी पति दीपक कुमार और अन्य परिवारजन के साथ विनयखंड-ई1/273 में रहती थी। पति दीपक कुमार मानसिक रूप से बीमार है। वर्तमान में निशा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोसाईगंज में संविदा पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थी। भाई सुमित ने बताया कि 19 मई की शाम निशा नाइट ड्यूटी की बात कहकर घर से निकली थी। इसके बाद वह पत्रकारपुरम स्थित विशाल मेगा मार्ट गई थी। शाम करीब 6:30 बजे निशा ने बेटी अयांशी को वीडियो कॉल की।

बातचीत में बेटी से कहा था कि वह जल्द ही उससे मिलने के लिए आएगी। बेटी से पूछा था कि उसे क्या चाहिए? बेटी ने बताया तो बोली कि आएंगे तो तुम्हारा गिफ्ट ले आएंगे। रात करीब आठ बजे निशा को काल किया तो मोबाइल फोन स्विच आफ मिला। उसे लगा कि नाइट ड्यूटी के कारण बहन ने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया होगा। 20 मई को भी लगातार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन मोबाइल बंद ही मिला।

कोई जानकारी न मिलने पर 21 मई की सुबह परिवारजन गोमतीनगर थाने पहुंचे और निशा की गुमशुदगी की तहरीर दी। इसी बीच 21 मई की देर शाम डायल-112 पर विकासखंड-4 ग्वारी इलाके में सुमित वैश्य के मकान से दुर्गंध आने की सूचना मिली। पुलिस दरवाजा खोलकर अंदर गई तो बेड पर निशा देवी का शव पड़ा हुआ था। शव सड़ चुका था। पुलिस की सूचना पर सुमित ने मौके पर पहुंच कर शव की शिनाख्त बहन निशा के रूप में की।

निशा ने 15 दिन पूर्व किराए पर रूम लिया था

मकान मालिक ने बताया कि निशा ने 15 दिन पूर्व किराए पर रूम लिया था। आसपास के कैमरे खंगाले तो दीपांशु हड़बड़ी में निकलता हुआ दिखा। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि निशा और वह नोवा अस्पताल में साथ में काम करते थे। वर्ष 2024 में दोनों में दोस्ती हो गई थी। इसके बाद दोनों काफी नजदीक आ गए थे। इंस्पेक्टर बृजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि आरोपित दीपांशु की जनवरी 2026 में शादी हो गई थी। इसके बाद से उसने निशा से दूरी बनाना शुरू कर दिया था।

निशा ने कमरा किराए पर लेकर उसके ऊपर साथ में रहने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इस बात को लेकर दोनों में आए दिन विवाद होने लगा था। आरोपी ने कबूला कि 19 मई को भी निशा ने उसे मिलने के लिए बुलाया और साथ में रहने का दबाव बनाया। इसपर उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। गुस्से में उसने निशा की गला दबाकर हत्या कर दी। परिवारजन का आरोप है कि निशा का मोबाइल फोन, अंगूठी और चेन गायब है।

मथुरा : बारात पर हिंसा! दुल्हन के भाई समेत 300 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज, कैसे क्या हुआ?

(जीएनएस)।

मथुरा जिले में 20 मई 2026 को एक दलित परिवार की शादी की बारात के दौरान हुई हिंसक झड़प ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 300 से अधिक लोगों पर केस दर्ज किए हैं, जिनमें दोनों पक्षों के 41 नामजद आरोपी शामिल हैं।

घटना हाईवे पुलिस थाना क्षेत्र के नरहौली गांव में हुई, जहां गोवर्धन क्षेत्र के भरना कलां गांव से आई बारात पर पथराव और मारपीट की घटनाएं सामने आईं। यह मामला जातीय संवेदनशीलता, शादी की रस्मों और ग्रामीण इलाकों में बढ़ते तनाव को एक बार फिर उजागर करता है।

घटना क्या थी?

भागवान दास की दो बेटियों 'लक्ष्मी और पूनम' की शादी नेमीचंद के बेटों अशोक और कुलदीप के साथ तय हुई थी। बारात 20 मई को शादी की रस्मों के लिए नरहौली गांव पहुंची। पुलिस के अनुसार, बारात जब गांव के ऊंची जाति वाले इलाके से गुजर रही थी, तभी विवाद शुरू हो गया। एक पक्ष का आरोप है कि बारात पर पत्थर फेंके गए, जिससे झड़प भड़क गई। वहीं दूसरे पक्ष ने दावा किया कि बारात के कुछ सदस्यों ने जाति-आधारित अपमानजनक गाने बजाए और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। जब स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई, तो बारात के सदस्यों ने कथित तौर पर उनके घरों में घुसकर तोड़फोड़ की और हमला कर दिया। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला शांति उर्फ संतोषी देवी घायल हो गईं। उनकी बहू राधा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस की कार्रवाईः 300+ पर केस

22 मई को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रोक कुमार ने बताया कि क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हाईवे पुलिस थाना के रल्हड शैलेंद्र सिंह के मुताबिकः

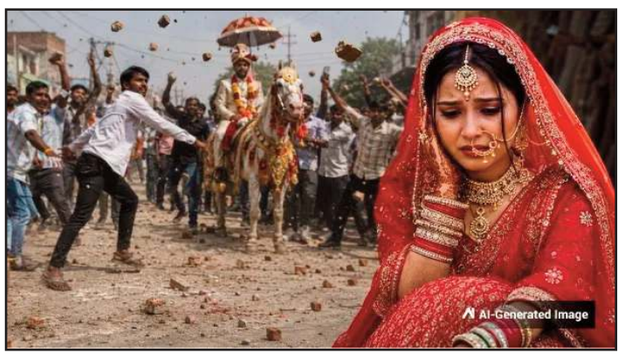

राधा की शिकायत पर 17 नामजद (दलित समुदाय के, जिसमें दुल्हन का भाई भी शामिल) और 250 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया।

दुल्हन के भाई दिलीप की शिकायत पर 24 नामजद और 20 अज्ञात पर केस।

कुल मिलाकर 300 से ज्यादा लोगों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए।

पुलिसकर्मियों पर हमले के अलग मामले में 15 नामजद और 50 अज्ञात पर केस दर्ज।

पुलिस ने एहतियात के तौर पर आसपास के कई थानों से अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है। दोनों समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है।

दोनों पक्षों के आरोप

पहला पक्ष (बारात/दलित परिवार):

बारात पर अनायास पत्थरबाजी की गई।

शादी की खुशी में आए लोगों को निशाना बनाया गया।

ऊंची जाति के लोगों ने जातीय भेदभाव दिखाते हुए हमला किया।

दूसरा पक्ष (स्थानीय ऊंची जाति के निवासी):

बारात के सदस्यों ने जातिसूचक गाली-गलौज भरे गाने बजाए।

आपत्ति जताने पर बारात ने हिंसा की और घरों में तोड़फोड़ की।

महिलाओं और बच्चों को भी डराया-धमकाया गया।

पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही है और किसी एक पक्ष को बचाने की बजाय निष्पक्ष जांच का दावा कर रही है।

घायलों की स्थिति और सबूत संग्रह

घायल बुजुर्ग महिला शांति देवी की हालत में सुधार हो रहा है। शुक्रवार शाम तक उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद है। पुलिस ने उउळश फुटेज, मोबाइल वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप्स की जांच शुरू कर दी है। रल्हड शैलेंद्र सिंह ने कहा कि हिंसा में शामिल हर व्यक्ति की पहचान इन फुटेज से की जाएगी। घटना के तीनों मुकदमों की जांच रक्ळ को सौंपे जाने की संभावना है, हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा बाकी है।

मथुरा में जातीय तनाव

मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में जातीय संवेदनशीलता हमेशा से रही है। शादी-ब्याह के मौकों पर छोटी-छोटी बातों से बड़े विवाद भड़क जाते हैं। इस घटना में डेटिंग ऐप या आधुनिक शादी नहीं, बल्कि पारंपरिक व्यवस्था में भी जातीय घर्षण सामने आया है।

सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं कि ऐसे मामलों में पुलिस को तुरंत और निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि छोटी घटना बड़े दंगे में न बदल जाए। पुलिस ने फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में बताते हुए दोनों पक्षों को संयम बरतने की सलाह दी है।

आगे क्या? SIT गठन और वीडियो फुटेज की फॉरेंसिक जांच।

नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी।

घायलों को मुआवजा और सुरक्षा।

लंबे समय में सामाजिक सद्भाव के प्रयास।

मथुरा प्रशासन ने दोनों समुदायों के बुजुर्गों और नेताओं से बातचीत शुरू कर दी है ताकि तनाव कम किया जा सके। यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि जाति आधारित पूर्वाग्रह अभी भी भारतीय समाज के ग्रामीण हिस्सों में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। शादी जैसे पावन अवसर पर हुई हिंसा न केवल दो परिवारों बल्कि पूरे इलाके की शांति को प्रभावित करती है।

यूपी में बाहुबलियों के हथियारों पर हाईकोर्ट का हथौड़ा, राजा भैया-बृजभूषण समेत 19 की बढ़ी टेंशन!

(जीएनएस)।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के शस्त्र लाइसेंसों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन समाज में डर पैदा करता है, जो कानून के शासन के बिल्कुल खिलाफ है।

अदालत ने राज्य सरकार और सभी जिलों के आला अधिकारियों से इस मामले में विस्तृत जवाब तलब करते हुए राजा भैया, धनंजय सिंह और बृजभूषण शरण सिंह समेत सूबे के 19 बड़े रसूखदारों के हथियारों की कुंडली मांग ली है। आइए जानतें हैं हाईकोर्ट के इस कड़े कदम के पीछे की पूरी कहानी क्या है। हाईकोर्ट ने यह तल्ख टिप्पणियां 'जय शंकर उर्फ बैरिस्टर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य' मामले में सूबे के भीतर निजी हथियारों के दुरुपयोग पर सुनवाई करते हुए कीं।

जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि, 'सच्ची आत्मरक्षा का उद्देश्य जीवन की रक्षा करना और व्यवस्था बनाए रखना होता है, न कि सार्वजनिक स्थलों को डर और दबदबे के माहौल में बदलना। इसलिए, जो संस्कृति बंदूकों और डराने-धमकाने को बढ़ावा देती है, उसे कभी भी शांतिपूर्ण और कानून सम्मत समाज के अनुकूल नहीं माना जा सकता।'

Bar and Bench की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने आगे जोड़ा कि जिस समाज में सशस्त्र व्यक्ति अपनी ताकत और धमकियों के दम पर दबदबा बनाते हैं, वह समाज कभी भी अधिक स्वतंत्र या शांतिपूर्ण नहीं बन सकता। अदालत ने साफ किया कि बिना सोचे-समझे हथियारों तक पहुंच समाज के लिए एक गंभीर खतरा है।

इस मामले में कोर्ट ने इसी साल मार्च महीने में ही उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलाधिकारियों (DM) और कलेक्टर्स को निर्देश दिया था कि वे अपने-अपने जिलों के सभी थानों के अनुसार निजी व्यक्तियों के पास मौजूद हथियारों का पूरा ब्योरा सौंपें। इसके साथ ही जिलाधिकारियों के पास लाइसेंस जारी करने, रिन्यू करने या ट्रांसफर करने के लिए लंबित पड़े आवेदनों की जानकारी भी मांगी गई थी।

कोर्ट के सामने जो आधिकारिक आंकड़े आए हैं, वे बेहद हैरान करने वाले हैंः कुल लाइसेंसः उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10,08,953 शस्त्र लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

लंबित आवेदनः वर्तमान में अलग-अलग श्रेणियों के 23,407 आवेदन पेंडिंग हैं।

पारिवारिक लाइसेंसः प्रदेश के

20,960 परिवार ऐसे हैं, जिनके पास एक से अधिक हथियार हैं।

आपराधिक रिकॉर्डः सबसे गंभीर बात यह है कि 6,062 मामलों में ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं, जिन पर दो या उससे ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

कोर्ट की रडार पर आए ये 19 रसूखदार

अदालत ने राज्य सरकार के गृह सचिव द्वारा दाखिल हलफनामे की समीक्षा के बाद कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने नोट किया कि एक तरफ राज्य सरकार गन कल्चर के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' (शून्य सहनशीलता) की नीति का दावा करती है, लेकिन दूसरी तरफ अधिकारियों ने व्यापक सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव रखने वाले राजनेताओं, सांसदों और विधायकों की महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाने की कोशिश की।

अदालत ने अब साफ तौर पर नाम लेकर इन 19 प्रभावशाली लोगों के सही पते, उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों, हथियार लाइसेंस और उन्हें मिली सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ब्योरा मांगा हैः

1. रघुराज प्रताप सिंह (राजा भैया)
2. धनंजय सिंह
3. बृजभूषण शरण सिंह
4. सुशील सिंह
5. विनीत सिंह
6. अजय मरहद
7. सुजीत सिंह बेलवा
8. उपेन्द्र सिंह गुड्डू
9. पप्पू भौकाली
10. इन्द्रदेव सिंह
11. सुनील यादव
12. फरार अजीम
13. बादशाह सिंह
14. संग्राम सिंह
15. सुल्लू सिंह
16. चुलबुल सिंह
17. सनी सिंह
18. छुन्नू सिंह
19. डॉ. उदय भान सिंह

PRGI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

ट्रेडिंग वॉर में घिर गए ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप पर पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति पर जंग से कमाई करने पर सवाल उठने लगे हैं। अब ट्रंप ट्रेडिंग वॉर में घिर गए हैं। नए वित्तीय खुलासों के अनुसार 2026 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2026 के बीच ट्रंप या उनके सलाहकारों की मंडली ने 3700 से ज्यादा शेयर सौदे किए। रोज लगभग 40 शेयर सौदे हुए। इनमें ट्रंप को लगभग 800 करोड़ रुपए यानी लगभग 83 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई हुई। ये शेयर एनवीडिया, बोइंग, माइव्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजन, ओरेकल और कॉस्टको जैसी वंपनियों के थे। ट्रंप विवादों में इसलिए हैं क्योंकि ये वंपनियां रक्षा सौदों, एआई नियमों और चिप और सेमीवंडक्टर आयात या फिर निर्यात से जुड़ी हुई हैं। वॉल स्ट्रीट की वंपनी एरिक प्रिंस के मुताबिक अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार है जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति वित्तीय लेन-देन और हितों के टकराव के मुद्दे पर सवालों के घेरे में है।

उधर व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर शेयर ट्रेडिंग को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगे आरोपों से इंकार किया है। ट्रंप आर्गेनाइजेशन पूरे कारोबार को संभालता है। बेटे जूनियर ट्रंप के पास अमेरिका और यूरोप से निवेश लाने की जिम्मेदारी है। जबकि दामाद जेरेड वुशनर की वंपनी एफिनिटी पार्टनर्स सउदी अरब और अन्य खाड़ी देशों के सरकारी वेल्थ पंड से मिले अरबों डालर के निवेश को संभालती है। इस रकम को शेयरों में डायवर्ड करते हैं। ट्रंप के पोर्टफोलियो में पिछले साल के अंतिम तीन महीनों में कई सौ शेयर ट्रेडिंग के रिकार्ड हैं। जबकि इस साल 10 फरवरी को ही ट्रंप ने माइव्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेजन में अपने शेयरों की हिस्सेदारी को बेचकर लगभग 350 करोड़ रुपए की कमाई की। इससे वुछ दिन पहले ही ट्रंप ने एंटी ट्रस्ट और एआई रेगुलेशन और डाटा नीतियों से संबंधित बड़े पैसले किए। ईरान युद्ध के दौरान ट्रंप के कभी युद्ध तो कभी वार्ता के बयानों से तेल और स्टॉक वायदा बाजारों में तेज उथल-पुथल रही। जब भी ट्रंप युद्ध का बयान देते तो तेल के दाम उछल जाते, जबकि वार्ता वाले बयान से शेयर बाजारों में तेजी आ जाती।

इमरान का तख्ता पलट अमेरिका की साजिश थी

अमेरिका की साजिश थी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार गिराने को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। लीक दस्तावेजों के आधार पर दावा किया गया है कि इमरान की वुसी सिर्प अविश्वास के प्रस्ताव से नहीं गिरी थी। इसके पीछे अमेरिकी साजिश और पाक सेना की भूमिका थी। दरअसल, इमरान ने 24 फरवरी 2022 को रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की थी। ठीक उसी दिन रूस ने यूव्रेन पर हमले शुरू किए थे।

रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इमरान की इस यात्रा से नाराज था। वह चाहता था कि पाकिस्तान यूव्रेन युद्ध पर रूस की खुलकर आलोचना करे, लेकिन इमरान सरकार ने तटस्थ रुख अपनाया। 7 मार्च 2022 को वाशिंगटन में पाक के तत्कालीन राजदूत असद मजीद खान और अमेरिकी सहायक विदेशी मंत्री डोनाल्ड लू के बीच बातचीत हुई। लू ने मजीद से कहा, यदि इमरान अविश्वास प्रस्ताव में टूट जाते हैं तो अमेरिका 'सब माफ' कर देगा। इसके 33 दिन बाद, 9 अप्रैल 2022 को इमरान सरकार गिर गई। वाशिंगटन के एक होटल में लू ने मजीद को लंच पर इमरान को हटाने का दबाव दिया था। इमरान के हटने के अगले दिन ही शाहबाज ने सत्ता संभाल ली। नवम्बर 2022 में जनरल बाजवा पद से सेवानिवृत हुए और आमी चीफ आसिम मुनीर का उदय हुआ। इमरान ने आरोप लगाया था कि मुनीर की नियुक्ति पूर्व पीएम नवाज शरीफ से परामर्श के बाद हुई थी। बाकी तो इतिहास है। अमेरिका किसी भी ऐसी सरकार को बर्दाश्त नहीं करता जो उसका विरोध करे और जिसकी रूस से नजदीकी हो।

लखनऊ का सहारा शहर अब बनेगा नया 'पॉवर सेंटर'! जानें कितनी बड़ी होगी यूपी की नई विधानसभा और क्या है सरकार का प्लान

(जीएनएस)।

लखनऊ के गोमती नगर स्थित 245 एकड़ के 'सहारा शहर' की जमीन पर अब उत्तर प्रदेश का नया और भव्य 'विधानभवन कॉम्प्लेक्स' बनेगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने इस प्रोजेक्ट की डिजाइन और प्लानिंग के लिए कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट के चयन हेतु टेंडर (RFP) जारी कर दिया है. 23 मई से 21 जून तक कंपनियां आवेदन कर सकेंगी. इस परिसर में विधानसभा के साथ आधुनिक सचिवालय, नया मुख्यमंत्री आवास और कई महत्वपूर्ण सरकारी दफ्तर भी बनाए जाएंगे.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब सत्ता का नया और सबसे बड़ा केंद्र तैयार होने जा रहा है. लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर में स्थित 'सहारा शहर' की जिस जमीन पर कभी सहारा साम्राज्य की धमक हुआ करती थी, अब वहां यूपी का भव्य और हाईटेक 'विधानभवन कॉम्प्लेक्स' आकार लेगा. लंबे समय से चल रही अटकलों और चर्चाओं पर आखिरकार शुक्रवार को आधिकारिक मुहर लग गई है. लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने इस महापरियोजना की डिजाइन और प्लानिंग के लिए कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट के चयन की प्रक्रिया शुरू करते हुए टेंडर जारी कर दिया है. इसके साथ ही यूपी को नया विधाभवन मिलने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है.

23 मई से शुरू होगी टेंडर

प्रक्रिया

एलडीए की ओर से जारी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के मुताबिक, देश-दुनिया की इच्छुक कंपनियां 23 मई से लेकर 21 जून तक इस प्रोजेक्ट के लिए अपने आवेदन जमा कर सकेंगी. आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट का चयन पूरा होने के बाद इस प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार की जाएगी. इस डीपीआर के आधार पर ही यह तय होगा कि नई विधानसभा को बनने में कुल कितना खर्च आएगा और इसे कितने समय में बनाकर पूरा किया जाएगा. एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि टेंडर जारी होने के बाद अब प्लानिंग के काम में तेजी आएगी.

सिर्फ विधानसभा नहीं, बनेगा पूरा 'पॉवर सेंटर'

हैरानी की बात यह है कि इस जमीन पर सिर्फ एक सरकारी इमारत नहीं खड़ी होगी, बल्कि सरकार का इरादा यहां एक पूरा प्रशासनिक हब बनाने का है. यही वजह है कि सरकारी दस्तावेजों और टेंडर में इसे सिर्फ 'विधानसभा' न कहकर 'विधानभवन कॉम्प्लेक्स' नाम दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक, 245 एकड़ के इस विशाल भूखंड पर नई विधानसभा के साथ-साथ एक बेहद आधुनिक सचिवालय, नया मुख्यमंत्री आवास और कई अन्य महत्वपूर्ण सरकारी विभागों के दफ्तर भी विकसित किए जाएंगे. जब यह बनकर तैयार हो जाएगा, तो शासन से जुड़े सभी बड़े फैसले और वीआईपी मूवमेंट इसी परिसर के भीतर होंगे.

यूपी सरकार काफी समय से नई विधानसभा के लिए एक बड़े और एकमुश्त भूखंड की तलाश में माथापच्ची कर रही थी. लखनऊ जैसे घने शहर के बीचों-बीच इतनी बड़ी जमीन मिलना लगभग असंभव सा लग रहा था. गोमती नगर की यह जमीन न सिर्फ आकार में बड़ी है, बल्कि इसकी लोकेशन और शहर के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी भी बेहद शानदार है. यही वजह है कि शासन स्तर पर हरी झंडी मिलने के बाद पिछले कुछ महीनों से यहाँ पैमाइश और तकनीकी सर्वे का काम गुपचुप तरीके से चल रहा था, जिसे अब टेंडर के जरिए सार्वजनिक कर दिया गया है.

1994 से शुरू हुआ विवाद और लीज रद होने की कहानी

इस जमीन का इतिहास भी बेहद दिलचस्प और विवादों से भरा रहा है. साल 1994-95 में लखनऊ नगर निगम ने सहारा इंडिया हाउसिंग लिमिटेड को 170 एकड़ जमीन 30 साल की लंबी अवधि के लिए पट्टे (लीज) पर दी थी. इस लीज की मुख्य शर्त यह थी कि सहारा समूह यहाँ एक सुंदर आवासीय कॉलोनी और ग्रीन बेल्ट (हरियाली क्षेत्र) विकसित करेगा. नियमों के मुताबिक, 130 एकड़ में कॉलोनी और 40 एकड़ में ग्रीन बेल्ट बनना था.

हालांकि, नगर निगम का आरोप था कि सहारा समूह ने लीज की शर्तों का जमकर उल्लंघन किया. न तो वादे के मुताबिक काम हुआ, न ही कई बार नोटिस देने के बावजूद सहारा ने लीज का नवीनीकरण (रिन्यूअल) कराया और न ही बकाया किराया जमा किया. पिछले साल जब 30 साल की यह अवधि पूरी हुई, तो नगर निगम ने लीज को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया और जमीन वापस अपने कब्जे में ले ली. वहीं, एलडीए ने भी अपनी 75 एकड़ जमीन पर पहले ही कब्जा वापस पा लिया था.

नवंबर 2025 में एलडीए के सर्वे ने बदली तस्वीर

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार को एक नया, आधुनिक और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से बड़ा विधानभवन बनाने के लिए कम से कम 200 एकड़ जमीन की जरूरत थी. शासन के निर्देश पर एलडीए ने नवंबर 2025 में सहारा शहर की खाली पड़ी इस जमीन का एक विस्तृत सर्वे किया था. सर्वे में पाया गया कि यहाँ तो सरकार की जरूरत से भी ज्यादा यानी पूरी 245 एकड़ जमीन उपलब्ध है, जो चारों तरफ से चौड़ी सड़कों और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से घिरी है. एलडीए ने तुरंत इसका प्रस्ताव शासन को भेजा, जिसे बिना देर किए मंजूर कर लिया गया. अब टेंडर जारी होने के साथ ही यूपी के इस ऐतिहासिक और सबसे आधुनिक निर्माण कार्य की उल्टी गिनती शुरू हो गई है.

योगी या अखिलेश? उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा चुनाव? मशहूर चुनावी पंडित की भविष्यवाणी से हलचल

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश की सियासत में 'दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है' वाली कहावत ऐसे ही नहीं मशहूर है। साल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से जोड़-तोड़ और कयासों का दौर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी सत्ता बचाने और बीजेपी की हैट्रिक लगाने की चुनौती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉमूर्ले के दम पर सत्ता में वापसी की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं।

राज्य की 403 विधानसभा सीटों पर होने वाली यह जंग इसलिए भी बेहद दिलचस्प है क्योंकि इसमें स्थानीय मुद्दों के साथ-साथ कानून-व्यवस्था, रोजगार और हालिया प्रशासनिक फैसलों की गूंज सुनाई दे रही है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड तक, सभी सियासी दल अपनी जमीन मजबूत करने के लिए रैलियां और जमीनी सर्वे कर रहे हैं, जिससे सूबे का सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है।

इखढ श्र रढ वढ एछएउळक्ढठ 2024

इसी बीच देश के सबसे मशहूर चुनावी विश्लेषक और सर्वे किंग प्रदीप गुप्ता (ढशीस्र ॠस्र३) ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। उनके इस नए विश्लेषण ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। आइए समझते हैं कि आखिर यूपी चुनाव 2027 को लेकर प्रदीप गुप्ता ने क्या बड़ी भविष्यवाणियां की हैं।

योगी सरकार से कितनी खुश है यूपी की जनता? जानिए जमीनी हकीकत

जब बात उत्तर प्रदेश की आती है, तो एंटी-इन्कंबेंसी (सरकार के खिलाफ माहौल) सबसे बड़ा फैक्टर होती है। लेकिन प्रदीप गुप्ता का आकलन कुछ और ही इशारा कर रहा है। उनका कहना है कि अगर हम जमीनी फीडबैक को समग्र रूप से देखें तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच संतुष्टि का स्तर काफी बेहतर है।

आसान शब्दों में कहें तो आज की तारीख में योगी सरकार के खिलाफ कोई बहुत बड़ी लहर, नाराजगी या बड़ी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि प्रदीप गुप्ता ने इसके साथ ही एक बड़ी चेतावनी भी जोड़ दी है। उनका कहना है कि यूपी की राजनीति का मिजाज बाकी राज्यों से एकदम अलग है। यहां कब पासा पलट जाए, कोई नहीं जानता। यूपी की जनता बहुत कम समय में अपना मूड बदलने के लिए जानी जाती है, इसलिए किसी भी दल को मुगालते में नहीं रहना चाहिए।

यूपी तक को दिए इंटरव्यू में प्रदीप गुप्ता का कहना है कि अगर कुल मिलाकर फीडबैक की बात करें, तो

उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार के प्रति जनता का 'संतुष्टि का स्तर' अच्छा है। कुल मिलाकर उनका कहना है कि इस चुनाव में भाजपा का पलड़ा ही भारी रहेगा। देखना ये होगा कि वो कितनी सीटों पर बदलता है।

जाति का गणित या विकास का काम: 2027 में किस पर वोट देगी जनता?

उत्तर प्रदेश के चुनावों में अक्सर कहा जाता है कि यहां 'वोट डाला नहीं जाता, बल्कि जाति पर वोट दिया जाता है'। इस पारंपरिक सोच पर प्रदीप गुप्ता ने एक बेहद सटीक और गहरी बात कही है। उनका मानना है कि यूपी की राजनीति से जाति (उं२३ी) का फैक्टर कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता, वह हमेशा रहेगा। लेकिन जीत-हार का फैसला सिर्फ जाति से नहीं होता।

आखिरकार, चुनाव का असली नतीजा सरकार के 'परफॉर्मेंस' यानी कामकाज पर ही आकर टिकता है। जनता अंत में यह देखती है कि सरकार ने बिजली, सड़क, पानी, कानून-व्यवस्था और राशन जैसी बुनियादी सुविधाओं पर कैसा काम किया है। अगर सरकार का काम उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो जाति का समीकरण भी धरा का धरा रह जाता है।

अखिलेश यादव के लिए क्या है प्रदीप गुप्ता का इशारा? विपक्ष का भविष्य

प्रदीप गुप्ता ने इस बात का भी बारीकी से विश्लेषण किया है कि अखिलेश यादव और विपक्ष की किस्मत कब और कैसे चमकेगी। उनके मुताबिक विपक्ष की जीत सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वे कितनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि इस बात पर करती है कि सत्ताधारी पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा है।

जनता वोट बदलते समय दो चीजें देखती है:

पहला-क्या मौजूदा सरकार का कामकाज खराब रहा है?

दूसरा-अगर मौजूदा सरकार ठीक नहीं है, तो विकल्प के रूप में सामने कौन खड़ा है और क्या वह इससे बेहतर शासन दे पाएगा?

जब तक बीजेपी और एनडीए (ठऊ्र) का प्रदर्शन कमजोर नहीं होता तब तक वे अपनी जीत का सिलसिला बनाए रखेंगे और विपक्ष चुनाव हारता रहेगा। ऐसी स्थिति में विपक्ष और अधिक हाशिए पर चला जाएगा।

सत्ता बदलने का '20 साल का चक्र': बीजेपी के लिए क्यों बड़ी चुनौती है बढ़ती उम्मीदें?

राजनीति के इतिहास का एक दिलचस्प पन्ना खोलते हुए प्रदीप गुप्ता यानी बदलाव के चक्र को समझाया। उन्होंने उदाहरण दिया कि देश में आजादी के बाद साल 1952 से लेकर 1977 तक लगातार करीब 25 सालों तक कांग्रेस ने एकछत्र राज किया, जिसके बाद बड़ा बदलाव आया। राजनीति में अमूमन 20 साल का एक ऐसा कालखंड होता है, जहां एक विचारधारा या दल स्थिर रहता है।

चूंकि बीजेपी को केंद्र और उत्तर प्रदेश में लगातार बड़े जनादेश मिले हैं, इसलिए जनता की उम्मीदें आसमान छू रही हैं। अब जबकि बिहार में भी एनडीए की मजबूत सरकार बन चुकी है, तो बीजेपी को खुद को नंबर वन बनाए रखने के लिए साधारण नहीं बल्कि 'सुपर परफॉर्मेंस' देना होगा। प्रदीप गुप्ता ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जब कोई पार्टी सफलता के सर्वोच्च शिखर पर होती है, तो उम्मीदों का दबाव भी सबसे ज्यादा होता है। इतिहास गवाह है कि जो बहुत ऊपर जाता है, वो बाद में थोड़ा नीचे भी आता है।

कांग्रेस की पुरानी गलतियां और विपक्ष की राह में 5 साल का रोड़ा

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को लेकर भी प्रदीप गुप्ता ने कड़ा विश्लेषण किया है। उनका मानना है कि कांग्रेस आज भी अपने पुराने 'मिस-गवर्नेंस' (खराब शासन) के दागों और लेगेसी इश्यूज से जूझ रही है, जिससे बाहर निकलने में उसे भारी मशक्कत करनी पड़ रही है।

अगर हम आने वाले साल 2029 के आम चुनाव की भी बात करें, तो देश और राज्य की जनता के दिलों में विकल्प के रूप में दोबारा भरोसा पैदा करने के लिए विपक्ष को कम से कम 5 साल का वक्त और लग सकता है।

भारत ने बनाया यूएस-चाइना की टक्कर का ड्रोन वायु अस्त्र-1, हवा में बदल सकता है टारगेट, कितनी रेंज-कितना सटीक हमला?

Nibe Limited ने राजस्थान के Pokhran Firing Range में अपनी स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम "वायु अस्त्र-1" की पहली टेक्निकल टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह टेस्ट नो-कॉस्ट, नो-कमिटमेंट (NCNC) प्रदर्शन के तहत किया गया, जिसमें इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफीसर और वैज्ञानिक भी मौजूद रहे।

कितनी रेंज और कितना सटीक हमला?

कंपनी और सेना के मुताबिक, यह टेस्ट भारतीय सेना द्वारा जारी किए गए 100 किलोमीटर रेंज वाले लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम के RFP के जवाब में किया गया था। टेस्ट के दौरान "Vayu Astra-1" ने 10 किलोग्राम वॉरहेड के साथ एंटी-पर्सनल स्ट्राइक मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया और 100 किलोमीटर दूर मौजूद लक्ष्य को एक ही बार में तबाह कर दिया।

कंपनी के मुताबिक, इस हथियार प्रणाली ने 1 मीटर से भी कम की Circular Error Probable (CEP) सटीकता हासिल की। इसका मतलब है कि हथियार लगभग बिल्कुल सटीक निशाने पर जाकर हमला करने में सक्षम है।

"Attack Cancel" और "Re-Attack" जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी

टेस्टिंग के दौरान "वायु अस्त्र-1" में कई एडवांस फीचर्स भी सफल पाए गए। इनमें हमला रद्द करने (Attack Cancel), दोबारा हमला करने (Re-Attack Capability) और इंटेलिजेंट टारगेट पेनिट्रेशन जैसी तकनीक शामिल हैं। वेपन एक्सपर्ट के मुताबिक, यह फीचर्स अगली पीढ़ी के ड्रोन और लोइटरिंग हथियारों के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं।

इजरायली तकनीक पर बेस्ड लेकिन भारत के लिए तैयार

अधिकारियों के मुताबिक, यह सिस्टम एडवांस इजरायली लोइटरिंग म्यूनिशन तकनीक पर आधारित है, लेकिन इसे भारतीय सेना की जरूरतों के हिसाब से विकसित और मॉडिफाई किया गया है।लोइटरिंग म्यूनिशन को आधुनिक युद्ध में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये दुश्मन के इलाके के ऊपर मंडरा सकते हैं, लक्ष्य की पहचान कर सकते हैं और बेहद सटीक हमला कर सकते हैं।

रात में भी सफल हमला, क्फ्र कैमरा से किया टारगेट लॉक

पोखरण टेस्टिंग के दौरान एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। कंपनी ने इन्फ्रारेड (IR) कैमरा-आधारित टारगेटिंग सिस्टम के जरिए रात में एंटी-आर्मर स्ट्राइक मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया।इस दौरान वेपन सिस्टम ने रात में 2 मीटर से कम CEP सटीकता के साथ लक्ष्य पर हमला किया।

70 किलोमीटर दूर से बदला गया कंट्रोल

टेस्ट के दौरान एक और हाई-टेक क्षमता दिखाई गई, जहां सिस्टम का कंट्रोल Ground Control Station(GCS) से लगभग 70 किलोमीटर दूर मौजूद Forward Control Station (FCS) में सफलतापूर्वक ट्रांसफर किया गया। वेपन एक्सपर्ट का कहना है कि यह क्षमता युद्ध के दौरान सेना की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और सर्वाइवल क्षमता को काफी बढ़ा सकती है। जिसके बाद इसकी तुलना अमेरिका, रूस, इजरायल और चीन के ड्रोन से हो रही है।

"Suryaastra" के बाद भारत की एक और बड़ी सफलता

"वायु अस्त्र-1" का यह सफल टेस्ट भारत की लंबी दूरी की सूर्यास्त्र" रॉकेट प्रणाली के हालिया सफल टेस्ट के कुछ दिनों बाद हुआ है। यह दिखाता है कि भारत स्वदेशी रक्षा तकनीक में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

"Make in India" रक्षा अभियान को मिला बड़ा बूस्ट

यह टेस्ट भारत की "Make in Inda" पहल के तहत स्वदेशी रक्षा तकनीक और प्रिसिजन-गाइडेड हथियारों में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि भारत अब मॉर्डन वॉरफेयर सिस्टम में तेजी से आत्मनिर्भर बनता जा रहा है।

निजी भारतीय कंपनियों की बढ़ती ताकत

डिफेंस इंडस्ट्रीज से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि "वायु अस्त्र-1" की सफलता इस बात का संकेत है कि अब निजी भारतीय कंपनियां भी एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी और सामरिक हथियारों के विकास में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। यह भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और भविष्य की सैन्य क्षमता के लिए बेहद सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

क्या स्टालिन बनेंगे मोदी सरकार के सीक्रेट पार्टनर? विजय सरकार पर नया खतरा! संसद में भाजपा खोज रही 360 का आंकड़ा

(जीएनएस)।

तमिलनाडु की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है, जहां चेन्नई की हलचल सीधे दिल्ली की सत्ता समीकरणों को प्रभावित करती दिख रही है। राज्य में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) की सत्ता जाने और टीवीके (TVK) प्रमुख थलपति विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि राजनीतिक रिश्तों का पूरा नक्शा बदलता नजर आ रहा है।

सबसे बड़ा झटका तब लगा, जब कांग्रेस ने डीएमके से दूरी बनाकर विजय सरकार के साथ जाने का फैसला किया। इस कदम ने डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को राजनीतिक तौर पर अलग-थलग कर दिया। अब चर्चा इस बात की है कि क्या बीजेपी इसी मौके का फायदा उठाकर डीएमके को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के करीब लाने की तैयारी कर रही है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या विजय सरकार की स्थिरता पर असर पड़ेगा?

तमिलनाडु में सत्ता बदली, तो दिल्ली का खेल भी बदल गया

तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से DMK और AIADMK के इर्द-गिर्द घूमती रही है। लेकिन इस बार समीकरण पूरी तरह बदल गए। टीवीके प्रमुख थलपति विजय के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ दिया और विजय सरकार को समर्थन दे दिया।

कांग्रेस के इस फैसले को सिर्फ राज्य स्तर का राजनीतिक बदलाव मानना बड़ी भूल होगी। इसके असर सीधे संसद तक दिखाई दे रहे हैं। डीएमके ने नाराज होकर विपक्षी इंडिया ब्लॉक से दूरी बना ली और लोकसभा में कांग्रेस से अलग बैठने के लिए स्पीकर को पत्र तक भेज दिया।

यहीं से बीजेपी की रणनीति शुरू होती दिख रही है। पार्टी को लग रहा है कि डीएमके अब विपक्षी राजनीति में पहले जैसी आक्रामक भूमिका में नहीं है और यही मौका उसे संसद में अपने बड़े एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की असली दिलचस्पी तमिलनाडु की राज्य राजनीति से ज्यादा संसद के नंबर गेम में है। डीएमके के पास लोकसभा में 22 सांसद और राज्यसभा में 8 सांसद हैं।

अगर ये समर्थन सीधे या मुद्दों के आधार पर एनडीए को मिल जाता है, तो बीजेपी संसद में उस ताकत के बेहद करीब पहुंच सकती है जिसकी उसे लंबे समय से तलाश है यानी दो-तिहाई बहुमत।

दरअसल केंद्र सरकार के सामने आने वाले समय में कई ऐसे बड़े विधेयक और संवैधानिक बदलाव हैं, जिनके लिए सिर्फ साधारण बहुमत काफी नहीं होगा।

इनमें सबसे ज्यादा चर्चा इन मुद्दों की है:

वन नेशन-वन इलेक्शन

परिसीमन विधेयक

महिला आरक्षण लागू करने से जुड़े संवैधानिक प्रावधान

न्यायिक सुधार

चुनावी सुधार

इन सभी मामलों में संविधान संशोधन की जरूरत पड़ सकती है और उसके लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई समर्थन जरूरी होता है। दो-तिहाई बहुमत BJP के लिए इतना अहम क्यों? लोकसभा में साधारण बहुमत से सरकार चल सकती है, लेकिन संविधान बदलने या बड़े ढांचागत सुधार लागू करने के लिए स्थिति अलग होती है। संविधान संशोधन विधेयक पास कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई समर्थन चाहिए।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनीं 150 लोगों की समस्याएं, कहा- सबकी समस्या का समाधान प्राथमिकता

गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने करीब 150 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं.

(जीएनएस)।

गोरखपुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में आए लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सबकी समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का निस्तारण तत्परता, पारदर्शिता और संवेदनशील ढंग से किया जाए. इसमें किसी भी तरह की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. हर समस्या का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपरक होना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन कार्यक्रम में सुनी 150 लोगों की समस्याएं

गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में

मुख्यमंत्री ने करीब 150 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. उन्होंने सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए शीघ्रता से समस्या समाधान के लिए निर्देशित किया. सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए. हर पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए उसकी त्वरित सहायता की जानी चाहिए. उन्होंने राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए.

जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए कई लोगों से मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसे के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए. इस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी.

सीएम योगी ने की गोसेवा, गोवंश को खिलाया गुड़

गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही. गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने तथा अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की प्रतिमा समक्ष शीश झुकाने के बाद वह मंदिर परिसर के भ्रमण पर निकले. गोशाला में पहुंचकर गोसेवा की. गायों और गोवंश को स्नेहिल भाव से गुड़ खिलाया. उन्होंने गोशाला के कार्यकताओं को भीषण गर्मी को देखते गोवंश की देखभाल के लिए जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए. मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए मुख्यमंत्री ने परिजनों के साथ आए बच्चों से बात की. उन्हें दुलारा-पुचकारा, आशीर्वाद के साथ चॉकलेट्स भी दीं.

लखनऊ में सरोजनी नगर थाना क्षेत्रांतर्गत ट्रक ने बाइक सवार तीन दोस्तों को रौंदा, दो की मौके पर मौत, ड्राइवर ट्रक लेकर भागा

घायल को लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ट्रक की तलाश कर रही है.

(जीएनएस)।

लखनऊ : सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया. तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने एक बाइक में ठोकर मार दी, जिससे एक ही बाइक पर सवार दो दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया. स्थानीय लोगों की मदद से घायल को आनन फानन लोक बंधु अस्पताल पहुंचाया गया. सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

सरोजनी नगर थाना प्रभारी राजदेव राम प्रजापति ने बताया, कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के अलीनगर सुनहरा निवासी संजय (45), वीरेंद्र (44) और इसी थाना क्षेत्र के नारायण पुरी निवासी कमल (45) शुक्रवार शाम करीब 7 बजे मजदूरी करके एक ही बाइक से सरोजनी नगर में बेहटवा गांव की तरफ से गिन्दन खेड़ा की ओर आ रहे थे.

सरोजनी के नादरगंज-अमौसी रेलवे स्टेशन रोड पर मेहराब ऑटो मूवर्स वर्कशॉप के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने उनकी बाइक में ठोकर मार दी, जिससे तीनों बाइक सहित नीचे गिर गए. इस हादसे में संजय और कमल की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि वीरेंद्र बुरी तरह घायल हो गया. घटना के बाद ट्रक चालक अपना वाहन लेकर मौके से भाग निकला.

स्थानीय लोगों ने 108 एंबुलेंस और सरोजनी नगर पुलिस को घटना की सूचना दी. सूचना के बाद पहुंची एंबुलेंस के जरिए स्थानीय लोगों की मदद से घायल वीरेंद्र को लोक बंधु अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मृतक संजय के परिवार में उसकी पत्नी देशवती के अलावा बेटा सूरज, अंकित और सौरभ है. वहीं कमल और वीरेन्द्र के परिवार में भी उनकी पत्नी के अलावा तीन बेटे हैं.

इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है. उनका कहना है कि यहां सड़क के किनारे दोनों तरफ ज्यादातर बड़े वाहन खड़े रहते हैं, जिससे रास्ता संकरा हो जाता है. इसके अलावा एलडीए द्वारा सड़क चौड़ीकरण के लिए दोनों तरफ नाला बनाया जा रहा है. एलडीए विभाग की लापरवाही से नाला की खुदाई कर उसकी मिट्टी दोनों तरफ रोड पर डाल दी गई है, जिसकी वजह से रास्ता संकरा हो गया है.

शुरू होगी लखनऊ, गोंडा, पैसेंजर ट्रेन, यात्रा होगी आसान

(जीएनएस)।

बाराबंकी रामनगर। कोरोना काल में बंद हुई नकहा-डालीगंज, लखनऊ पैसेंजर ट्रेन सेवा छह साल बाद दोबारा शुरू होने जा रही है। इस सेवा का शुभारंभ 26 मई से होगा। रेलवे ने इस ट्रेन को लखनऊझगोंडाझबुढ़वल, बिंदौरा, बाराबंकी मार्ग से चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है।

ट्रेन का संचालन शुरू होने पर बुढ़वल समेत आसपास के जिलों के यात्रियों को लखनऊ, सीतापुर और गोंडा तक जाने में सुविधा मिलेगी। जनप्रतिनिधियों ने इस ट्रेन को दोबारा चलाने के लिए रेलवे अधिकारियों से पत्राचार किया था। पंकज कुमार श्रीवास्तव ने बताया, रेलवे बोर्ड ने प्रस्तावित शेड्यूल जारी किया है। संचालन शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है।

प्रस्तावित समय सारिणी के अनुसार, ट्रेन संख्या 55062 डालीगंज झलखनऊ से 26 मई से संचालित होगी। वहीं, ट्रेन संख्या 55061 नकहा जंगल से 27 मई से चलेगी। यह ट्रेन सुबह 05:42 बजे गोंडा जंक्शन पहुंचेगी और 09:25 बजे डालीगंज (लखनऊ) पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 55062 डालीगंज से शाम 05:20 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 04:45 बजे नकहा जंगल पहुंचेगी। ट्रेन में एसएलआर और जनरल श्रेणी सहित कुल 12 कोच लगाए जाएंगे।

पेट्रोल-डीजल फिर होगा महंगा? होर्मुज पर देना होगा टोल, क्या है ईरान का प्लान?

(जीएनएस)।

मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अब ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा संकेत दिया है। ईरान और ओमान इस अहम समुद्री रास्ते पर स्थायी टोल सिस्टम बनाने पर चर्चा कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई महंगी पड़ सकती है। होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल और एलएनजी गुजरता है।

ईरान का कहना है कि सुरक्षा और समुद्री ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए खर्च होता है, इसलिए जहाजों को फीस देनी होगी। अमेरिका और खाड़ी देशों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। सवाल है कि क्या इससे पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमतें फिर बढ़ेंगी?

क्या है ईरान-ओमान का नया प्लान

क्र्ल्ल और डेंल्ल होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को लेकर नया ढांचा तैयार करने पर बात कर रहे हैं। ईरान चाहता है कि इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से तय फीस ली जाए। उसका तर्क है कि सुरक्षा, निगरानी और समुद्री ट्रैफिक कंट्रोल पर भारी खर्च आता है। फ्रांस में ईरानी राजदूत मोहम्मद अमीन नेजाद ने भी कहा कि जो देश और कंपनियां इस रास्ते का इस्तेमाल करती हैं, उन्हें इसका हिस्सा चुकाना चाहिए। हालांकि ओमान ने अभी तक इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा है।

दुनिया के लिए इतना अहम क्यों है होर्मुज

दुनिया के सबसे अहम समुद्री रूट्स में गिना जाता है। फारस की खाड़ी से निकलने वाला तेल और एलएनजी इसी रास्ते से एशिया और यूरोप तक पहुंचता है। दुनिया के करीब 20 फीसदी तेल कारोबार का रास्ता यही है। यही वजह है कि यहां किसी भी तनाव का असर सीधे ग्लोबल मार्केट पर पड़ता है। अगर यहां टोल लगता है या जहाजों की आवाजाही धीमी होती है, तो तेल कंपनियों का खर्च बढ़ेगा और उसका असर आम लोगों तक पहुंचेगा।

अमेरिका-इजरायल हमले के बाद बदला माहौल

वल्र्३ीी र३३ीर और क२१ी' के साथ बढ़े तनाव के बाद ईरान ने होर्मुज में अपनी पकड़ और मजबूत करनी शुरू कर दी है। फरवरी में हुए हमलों के बाद ईरान ने कई जहाजों की आवाजाही रोक दी थी। अब तेहरान इसे अस्थायी कदम नहीं बल्कि स्थायी रणनीति बनाना चाहता है। ईरान का कहना है कि उसकी सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी वजह से वह समुद्री रास्ते पर औपचारिक नियंत्रण और फीस सिस्टम लागू करने की तैयारी में है।

तेल-गैस की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा

अगर होर्मुज स्ट्रेट में स्थायी टोल सिस्टम लागू होता है तो सबसे बड़ा असर तेल और गैस की कीमतों पर दिख सकता है। जहाज कंपनियों को अतिरिक्त फीस देनी पड़ेगी, जिससे ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ेगी। इसका असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। भारत जैसे देश, जो बड़ी मात्रा में तेल आयात करते हैं, वहां पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस महंगी हो सकती है। एक्सपर्ट मानते हैं कि सिर्फ तनाव की खबर से ही बाजार में कीमतें ऊपर जाने लगती हैं।

ईरान का सख्त संदेश और बढ़ी चिंता

ईरान साफ कर चुका है कि होर्मुज स्ट्रेट पर उसका रुख नहीं बदलेगा। ईरानी संसद में भी इससे जुड़ा प्रस्ताव पास किया जा चुका है। तेहरान का कहना है कि इस इलाके की सुरक्षा उसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दूसरी तरफ खाड़ी देश और पश्चिमी ताकतें इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खतरा मान रही हैं। अगर आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सहमति नहीं बनी तो मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है। इसका असर सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी दिखेगा।

ऊर्जा विभाग ने लखनऊ में उतारी अधिकारियों की फौज; जिलों से बुलाए गए 44 अधिशासी अभियंता

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने अधिकारियों की तत्काल तैनाती के निर्देश दिए हैं.

(जीएनएस)।

लखनऊः राजधानी लखनऊ में भीषण बिजली कटौती से सरकार की किरकिरी हो रही है. जगह-जगह लोगों का विरोध भी देखने को मिल रहा है. आम जनता और नेताओं के निशाने पर बिजली विभाग के अधिकारी हैं.

वर्टिकल व्यवस्था लागू होने की वजह से बिजली कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई थी. इससे बाधित हुई बिजली आपूर्ति को दुरुस्त करने में समय लग रहा है. बिजली संकट ज्यादा बढ़ रहा है. इस समस्या को दूर करने के लिए विभिन्न जिलों से अधिशासी अभियंताओं का ट्रांसफर कर लखनऊ के विभिन्न उपकेंद्रों पर तैनात कर दिया गया है. विभिन्न जिलों से 44 अधिशासी अभियंता लखनऊ बुलाए गए हैं.

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने सख्त पर निर्देश दिया है कि जिन अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है, उनको तत्काल तैनाती स्थल से कार्यमुक्त कर दिया जाए. इसमें किसी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं होगी.

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष व अपर मुख्य सचिव डॉ. आशीष गोयल ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की समीक्षा की थी. अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि राजधानी में बिजली आपूर्ति व्यवस्था हर हाल में पटरी पर लाई जाए. इसके लिए किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अध्यक्ष के सख्त निर्देश के बाद अब मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने लखनऊ में फील्ड पर अधिकारियों के फौज उतार दी है.

शाहजहांपुर के अधिशासी अभियंता केश कुमार को अमौसी क्षेत्र में मुख्य अभियंता वितरण बनाया गया है. अंकित सिंह राजपूत को अधिशासी अभियंता गोला से मुख्य अभियंता वितरण जानकीपुरम क्षेत्र, सुरेश वर्मा को बदायूं से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र, दीपक सोनी को शाहजहांपुर से मुख्य अभियंता वितरण अमौसी क्षेत्र, संदीप कुमार यादव को महाराजगंज से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र बनाया गया है.

अंकित वर्मा को निघासन से मुख्य अभियंता वितरण अमौसी क्षेत्र, शेषराम यादव को बरेली से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र, अविनाश कुमार निषाद को महाराजगंज से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र, नीरज कुमार पांडेय को मिल्कीपुर से मुख्य अभियंता वितरण अमौसी क्षेत्र, यश गुप्ता को जलालाबाद से मुख्य अभियंता वितरण अमौसी क्षेत्र, प्रेम कुमार साहू को जलालाबाद से मुख्य अभियंता वितरण अमौसी क्षेत्र बनाया गया है.

इसके अलावा बरेली से अवनीश कुमार यादव को मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र, अभिमन्यु सिंह को मोहम्मदी से मुख्य अभियंता वितरण गोमती नगर क्षेत्र, विपिन कुमार वर्मा को नानपारा से मुख्य अभियंता वितरण जानकीपुरम क्षेत्र, संदीप कुशवाहा को मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र, उमेश पाल को शाहजहांपुर से मुख्य अभियंता वितरण अमौसी क्षेत्र, सुरेंद्र कुमार को सीतापुर से मुख्य अभियंता वितरण अमौसी क्षेत्र, गोविंदा गौतम को महमूदाबाद से मुख्य अभियंता वितरण अमौसी क्षेत्र, अहमद राजा को हैदरगढ़ से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र बनाया गया है.

प्रदोष कुमार को गौरीगंज से मुख्य अभियंता वितरण जानकीपुरम क्षेत्र, महेंद्र वर्मा को सुल्तानपुर से मुख्य अभियंता वितरण गोमती नगर क्षेत्र, अक्षय शुक्ला को उन्नाव से मुख्य अभियंता वितरण जानकीपुरम क्षेत्र, नीरज कुमार सिंह को उन्नाव से मुख्य अभियंता वितरण अमौसी क्षेत्र, रामाधीन को बरेली से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र, संजीव कुमार को मुख्य अभियंता वितरण जानकीपुरम क्षेत्र, अवनीश कुमार यादव को बरेली से मुख्य अभियंता लखनऊ मध्य क्षेत्र बनाया गया है.

अमन कुमार शास्त्री को महमूदाबाद से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र, आनंद कुमार गुप्ता को शाहजहांपुर से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र, नितेश कुमार प्रजापति को बरेली क्षेत्र से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र, अनिल कुमार चौहान को बरेली क्षेत्र से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र, अश्विनी कुमार विश्वकर्मा को कैसरगंज से मुख्य अभियंता वितरण गोमती नगर क्षेत्र, रंजीत कुमार को कैसरगंज से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र बनाया गया है.

संदीप कुमार श्रीवास्तव को शाहजहांपुर से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र, संजय कुमार सिंह को बदायूं से मुख्य अभियंता वितरण जानकीपुरम क्षेत्र, जितेंद्र मौर्य को पीलीभीत से मुख्य अभियंता जानकीपुरम क्षेत्र, दीपक कश्यप को बीसलपुर से मुख्य अभियंता वितरण अमौसी क्षेत्र, भागीरथी राजभर को मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र बनाया गया है.

मोहम्मद रिजवान को बिसौली से मुख्य अभियंता वितरण जानकीपुरम क्षेत्र सोनू कुमार को बिल्सी से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र रोहित शर्मा को बदायूं से मुख्य अभियंता वितरण जानकीपुरम क्षेत्र, दीपक कुमार वर्मा को गोला से मुख्य अभियंता वितरण जानकीपुरम क्षेत्र, मनोज कुमार को संडीला से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र, मनीष कुमार को नानपारा से मुख्य अभियंता वितरण अमौसी क्षेत्र और कन्हैया लाल यादव को नानपारा से मुख्य अभियंता वितरण जानकीपुरम क्षेत्र में तैनाती दी गई है.

'पेपर लीक नहीं हुआ, बस सवाल बाहर आ गए', संसदीय समिति के सवाल पर एनटीए चीफ का अजीबोगरीब बयान

(जीएनएस)।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के प्रमुख अभिषेक सिंह ने संसद की स्थायी समिति के सामने कहा कि NEET-UG 2026 का पेपर NTA के सिस्टम से लीक नहीं हुआ था, बल्कि "कुछ सवाल बाहर आ गए थे।" इसी बयान को लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। समिति ने ठळअ से पूछा कि आखिर इतनी बड़ी परीक्षा में सुरक्षा चूक कैसे हुई और भविष्य में इसे कैसे रोका जाएगा।

इस बीच CBI पूरे मामले की जांच कर रही है और अब दोबारा परीक्षा 21 जून को कराई जाएगी। NEET विवाद को लेकर छात्रों और अभिभावकों की चिंता अभी भी बनी हुई है।

Abhishek Singh ने संसदीय समिति को बताया कि पेपर सीधे NTA सिस्टम से लीक नहीं हुआ। उनके मुताबिक, कुछ सवाल परीक्षा से पहले बाहर पहुंच गए थे और इसी वजह से परीक्षा रद्द करनी पड़ी। हालांकि विपक्ष और कई छात्र संगठन इसे "पेपर लीक" ही बता रहे हैं। NTA का कहना है कि एजेंसी की डिजिटल सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगी। अब इस बयान के

बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है कि आखिर "सवाल बाहर आना" और "पेपर लीक" में फर्क क्या है।

संसद समिति ने पूछे सख्त सवाल

समिति के सदस्यों ने ठळअ अधिकारियों से परीक्षा प्रक्रिया की मजबूती को लेकर कई सवाल किए। खासकर अगले साल से NEET को कंप्यूटर बेस्ड करने की तैयारी पर चर्चा हुई। सदस्यों ने पूछा कि इतने बड़े स्तर पर ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। परीक्षा की सुरक्षा, सेंटर मैनेजमेंट और तकनीकी व्यवस्था पर भी सवाल उठे। समिति ने यह भी जानना चाहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या नए कदम उठाए जा रहे हैं।

CBI जांच और दोबारा परीक्षा पर फोकस

सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। NEET-UG परीक्षा 3 मई को हुई थी, लेकिन आरोप सामने आने के बाद 12 मई को इसे रद्द कर दिया गया। अब दोबारा परीक्षा 21 जून को होगी। सरकार ने कहा है कि इस बार सुरक्षा के ज्यादा कड़े इंतजाम किए जाएंगे। 22 लाख से ज्यादा छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे, इसलिए किसी भी तरह की गड़बड़ी को लेकर भारी दबाव बना हुआ है।

NTA में करीब 25 प्रतिशत पद खाली,

बैठक में यह भी सामने आया कि NTA में करीब 25 प्रतिशत पद खाली हैं। अधिकारियों ने समिति को बताया कि नई नियुक्तियों और ढांचे में सुधार की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही के. राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों में से करीब 75 प्रतिशत लागू किए जाने का दावा भी किया गया। सरकार चाहती है कि भविष्य में NTA की परीक्षा प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बने।

हालांकि NEET विवाद के बाद एजेंसी की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने मचाया तहलका, ओपनिंग डे पर की इतनी कमाई

(जीएनएस)।

सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों की दुनिया में 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी का नाम अब सिर्फ एक फिल्म सीरीज नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। यही वजह है कि जैसे ही मोहनलाल स्टारर 'दृश्यम 3' सिनेमाघरों में रिलीज हुई, फैंस का उत्साह देखने लायक था। निर्देशक जीतू जोसेफ की इस बहुप्रतीक्षित फिल्म ने गत 21 मई 2026 को मोहनलाल के 66वें जन्मदिन के खास मौके पर थिएटरों में दस्तक दी और रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत दर्ज कर ली।

मोहनलाल की क्राइम-थ्रिलर ने मचाया हंगामा

हालांकि फिल्म अपने पहले दिन 'एल2: एम्पुरान' और 'दृश्यम 2' जैसी बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाई लेकिन इसके बावजूद इस क्राइम-थ्रिलर ने शानदार कमाई करते हुए मोहनलाल की हालिया कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।

ओपनिंग डे पर 'दृश्यम 3' ने की करोड़ों की कमाई

-रिलीज से पहले ही फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ था। एडवांस बुकिंग से लेकर सोशल मीडिया तक फिल्म की खूब चर्चा रही और इसका असर ओपनिंग डे कलेक्शन में साफ देखने को मिला। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने भारत में पहले दिन लगभग 15.85 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।

-फिल्म को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स मलयालम वर्जन में मिला, जहां से करीब 13.70 करोड़ रुपये की कमाई हुई। वहीं तेलुगू मार्केट से 1.50 करोड़, तमिल से 45 लाख और कन्नड़ भाषा से लगभग 20 लाख रुपये का कलेक्शन आया। पहले दिन फिल्म की ऑक्यूपेंसी 51 प्रतिशत से ज्यादा दर्ज की गई जो एक थ्रिलर फिल्म के लिए काफी मजबूत मानी जा रही है।

ओवरसीज में भी छाया 'दृश्यम 3' का जादू

-भारत ही नहीं विदेशों में भी मोहनलाल की इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। खासतौर पर खाड़ी देशों, अमेरिका और यूरोप में फिल्म ने शानदार शुरुआत की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 'दृश्यम 3' ने ओवरसीज मार्केट में पहले ही दिन करीब 25 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है।

-इसी के साथ फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन पहले दिन 43 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। इतनी बड़ी ओपनिंग के बाद अब ट्रेड एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि फिल्म पहले वीकेंड में कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकती है।

-पहले ही दिन की कमाई के दम पर फिल्म 'दृश्यम 3' ने साल 2026 की टॉप ग्रॉसिंग मलयालम फिल्मों की सूची में अपनी जगह बना ली है। फिल्म ने कई चर्चित फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है और अब तेजी से ऊपर बढ़ती नजर आ रही है।

-ट्रेड विश्लेषकों का मानना है कि अगर फिल्म इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में ये साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन सकती है। दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर जो क्रेज दिख रहा है, उससे साफ है कि इसका बॉक्स ऑफिस सफर अभी लंबा चलने वाला है।

दर्शकों का मिला-जुला रिस्पॉन्स पर मोहनलाल की एक्टिंग की हुई तारीफ

-फिल्म को लेकर दर्शकों और क्रिटिक्स की राय थोड़ी अलग-अलग नजर आई है। कई लोगों ने फिल्म के सस्पेंस और मोहनलाल की दमदार परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की है जबकि कुछ दर्शकों को कहानी का ट्रीटमेंट और प्लॉट उतना प्रभावशाली नहीं लगा है।

-इसके बावजूद एक बात पर लगभग सभी सहमत दिखे कि जॉर्जकुट्टी के किरदार में मोहनलाल एक बार फिर पूरी तरह छा गए हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और इमोशनल इंटेंसिटी फिल्म को मजबूत बनाती है।

पुरानी स्टारकास्ट की वापसी ने बढ़ाया एक्साइटमेंट

-'दृश्यम 3' में एक बार फिर वही स्टारकास्ट नजर आई है जिसने इस फ्रेंचाइजी को यादगार बनाया है। फिल्म में मोहनलाल के साथ मीना, अंसीबा हसन, एस्थर अनिल, मुरली गोपी, सिद्दीकी और आशा सरत अपने पुराने किरदारों में लौटे हैं।

-फिल्म की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां 'दृश्यम 2' खत्म हुई थी। इस बार कहानी में और ज्यादा सस्पेंस, इमोशन और माइंड गेम देखने को मिलते हैं, जिसने फैंस की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है।